



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2017/ज्येष्ठ 31, 1939

No. 510]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2017/JYAISTHA 31, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2017

सं. 55/2017-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 619(अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उप-धारा (1), सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और धारा 156 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ.— (1) इन नियमों को भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,-

(क) “महानिदेशक” से अभिप्राय सीमा-शुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक (रक्षोपाय) से है;

(ख) “घरेलू उद्योग” से अभिप्राय आयातित वस्तुओं के संबंध में ऐसे उत्पादकों से है,

(i) जो कि इस प्रकार की वस्तुओं का समग्र रूप से या उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक हों; या

(ii) जिनका इसी प्रकार की वस्तुओं का सामूहित उत्पादन या भारत में प्रत्यक्षता प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुओं का उत्पादन भारत में होने वाले इस प्रकार के वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पाद का बहुत बड़ा अनुपात होता है;

- (ग) “वस्तुओं” से अभिप्राय किसी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं, उत्पादों, सामानों या सामग्री से है;
- (घ) “आयात वृद्धि” से अभिप्राय मलेशिया से होने वाले आयात में वृद्धि से है। चाहे इसे निरपेक्ष रूप में देखा जाए या घरेलू उत्पादन से तुलनात्मक रूप से।
- (ङ.) “इच्छुक पक्षकार”
- (i) मलेशिया का कोई उत्पादक या निर्यातक या ऐसे वस्तु का आयातकर्ता जो कि द्विपक्षीय रक्षोपाय के लिए जांच के अधीन हो। या कोई व्यापारी या व्यापारिक समुदाय जिसके ज्यादातर सदस्य ऐसे वस्तुओं के उत्पादक हों, निर्यातक हों या आयातकर्ता हों;
- (ii) मलेशिया सरकार; और
- (iii) इसी प्रकार की वस्तु या ऐसी वस्तु जो भारत में प्रत्यक्षता प्रतिस्पर्धात्मक हो, के उत्पादक या व्यापारी या व्यापारी समुदाय जिसके ज्यादातर सदस्य ऐसी वस्तुओं का या उन वस्तुओं का जो भारत में प्रतिस्पर्धात्मक हो का उत्पादन या व्यापार करते हों;
- (च) “इसी प्रकार की वस्तुओं” से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जो कि जांच के अधीन वस्तुओं के हर प्रकार से सादृश्य हो या उसी की तरह ही हो;
- (छ) “मूल वस्तु” से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 43/2011-सीमा-शुल्क (गै.टे.), दिनांक 01 जुलाई, 2011, जिसे सा.का.नि. 500(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2011 के तहत प्रकाशित किया गया था, के तहत अधिसूचित सीमा शुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और मलेशिया की सरकारों के बीच अधिमान्य व्यापार करार के अंतर्गत माल के उद्गम का निर्धारण) नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत मूलतः उत्पादित वस्तुओं से संबंधित अर्हता को पूरी करते हों।
- (ज) “गम्भीर क्षति” से अभिप्राय घरेलू उद्योग के खास तथा सकल नुकसान से है;
- (झ) “गम्भीर क्षति के खतरे” से अभिप्राय गम्भीर क्षति के ऐसे तात्कालिक खतरे से है जो कि तथ्यों पर आधारित हों न कि आरोप, अटकलबाजी या दूरवर्ती सम्भावना पर आधारित हों;
- (ञ) “व्यापार करार” से अभिप्राय भारत गणराज्य और मलेशिया सरकार के बीच बृहद आर्थिक सहयोग करार से है।
- (2) यहां प्रयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) और सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) में परिभाषित किया गया है, का क्रमशः वही अभिप्राय होगा जोकि उन्हें इन अधिनियमों में दिया गया है।
- 3. महानिदेशक के कर्तव्य.—** महानिदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वे,-
- (क) इस प्रकार की जांच पड़ताल करें कि क्या व्यापार करार के अंतर्गत सीमा-शुल्क में कटौती अथवा इसे समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में मूलभूत वस्तुओं के बढ़ते हुए आयात के कारण भारत के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है अथवा गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है;
- (ख) वस्तुगत और परिमाणिक प्रकृति के उन सभी कारकों का मूल्यांकन करेंगे जिनका प्रभाव घरेलू उद्योग की स्थिति पर, विशेषकर इन मूलतः उत्पादित वस्तुओं के आयात की निरपेक्ष या सापेक्ष दर या मात्रा, घरेलू बाजार में हिस्सा जो कि मूलतः उत्पादित वस्तुओं के आयात में होने वाली वृद्धि से हुआ हो, बिक्री के स्तर, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग लाभ और हानि तथा रोजगार पड़ता हो;

- (ग) केंद्र सरकार को अनंतिम अथवा अन्यथा रूप से अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करे कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमा-शुल्क में कटौती अथवा इसे समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप मलेशिया से भारत में मूलभूत वस्तुओं के बढ़ते हुए आयात के कारण भारत के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है अथवा गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है;
- (घ) ऐसे द्विपक्षीय रक्षोपायों की सिफारिश करें जिनको यदि अपनाया जाए तो वे गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए पर्याप्त हों;
- (ङ.) द्विपक्षीय रक्षोपायों की अवधि के बारे में सिफारिश करें और जहां एक साल से अधिक की अवधि के लिए इनकी सिफारिश की गई हो वहां इसके समायोजन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक उत्तरोत्तर उदारीकरण की सिफारिश करें; और
- (च) द्विपक्षीय रक्षोपायों को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा।

4. जांच का प्रारंभ.—(1) महानिदेशक इस प्रकार की वस्तुओं या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों से या उनकी ओर से प्राप्त होने वाले लिखित आवेदन पर यह निर्धारित करने के लिए जांच शुरू करवाएंगे कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमा-शुल्क में कटौती अथवा इसे समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में मूलभूत वस्तुओं के बढ़ते हुए आयात के कारण भारत के घरेलू उद्योग को कितनी गंभीर क्षति पहुंची है अथवा कितनी गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए किसी भी आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा,-

(क) निम्न के बारे में प्रमाण -

- (i) मूलभूत वस्तुओं का बढ़ा हुआ आयात;
- (ii) घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का खतरा;
- (iii) आयात और तथाकथित गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच आकस्मिक संबंध; और
- (iv) व्यापार करार के अनुक्रम में सीमा-शुल्क में की गई कटौती या उसे समाप्त किया जाना जिससे मूलभूत वस्तुओं का आयात बढ़ा हो और इस प्रकार बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को काफी क्षति पहुंची हो।

बशर्ते यह जरूरी नहीं कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमा-शुल्क में की गई कटौती या उसको समाप्त किए जाने के अन्य किसी कारण के बराबर या उससे बड़ा हो; और

(ख) आयात प्रतिस्पर्धा में समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों या किए जाने के लिए नियोजित प्रयासों अथवा दोनों का एक विवरण।

(3) महानिदेशक उप-नियम (1) के अंतर्गत दिए गए आवेदन पर तब तक कोई जांच कार्य शुरू नहीं करेंगे जब तक कि वे आवेदन में दिए गए साक्ष्यों की शुद्धता और पर्याप्तता की जांच नहीं कर लेते हैं और इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि इसमें निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं-

- (क) मूलभूत वस्तुओं का बढ़ा हुआ आयात;
- (ख) गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का खतरा;
- (ग) मूलभूत वस्तुओं के आयात और तथाकथित गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच कोई आकस्मिक संबंध; और
- (घ) व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में की गई कटौती या उसको समाप्त किए जाने के कारण मूलभूत वस्तुओं के आयात में होने वाली पर्याप्त बढ़ोत्तरी:

बशर्ते कि, कोई जरूरी नहीं है कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमा-शुल्क में की गई कटौती या इसको समाप्त किए जाने का जो कारण है वह अन्य किसी कारण के बराबर ही हो या उससे अधिक हो।

(4) उप-नियम (1) में निहित किन्हीं भी बात के अलावा महानिदेशक, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त किए गए किसी प्रधान सीमा-शुल्क आयुक्त अथवा सीमा-शुल्क आयुक्त से अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि उप-नियम (3) के उपवाक्य (क), उपवाक्य (ख), उपवाक्य (ग) और उपवाक्य (घ) में संदर्भित साक्ष्य पर्याप्त हैं तो वे अपनी ओर से जांच कार्य शुरू कर सकते हैं।

5. जांच से संबंधित सिद्धांत.- (1) महानिदेशक द्वारा, व्यापार करार के अंतर्गत सीमा-शुल्क में कटौती किए जाने अथवा इसे समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में मूलभूत वस्तुओं के बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई गम्भीर क्षति या क्षति के खतरे का आकलन करने के लिए जांच पड़ताल प्रारंभ किए जाने के निर्णय लेने के बाद वह अपने इस निर्णय को अधिसूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे और इस सार्वजनिक सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त जानकारी होगी, अर्थात:-

- (क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत मूलभूत वस्तुओं, जांच और इनके वर्गीकरण के अध्यधीन इनका स्पष्ट विवरण;
 - (ख) जांच पड़ताल शुरू किए जाने की तारीख;
 - (ग) जांचाधीन अवधि;
 - (घ) उन तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण जिनके आधार पर गम्भीर क्षति के आरोप अथवा गंभीर क्षति के खतरे की बात कही गई है;
 - (ङ.) जांच को शुरू किए जाने के कारण;
 - (च) वह पता जहां कि इच्छुक पक्षकारों के अभ्यावेदनों को भेजा जाना है; और
 - (छ) इच्छुक पक्षकारों को यथोचित माध्यमों के द्वारा अपने विचार को व्यक्त करने के लिए दी गई समय-सीमा।
- (2) महानिदेशक इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रसारित करेंगे :-
- (क) केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय जिनको वे उचित समझे;
 - (ख) संबंधित व्यापार संघ अथवा उस मूलभूत वस्तु का अभिज्ञात निर्यातक जिसके बढ़े हुए निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति होने या क्षति होने का खतरा पैदा होने की बात कही गई है;
 - (ग) मलेशिया सरकार; और
 - (घ) अन्य इच्छुक पक्षकार जिसको महानिदेशक उचित समझे।
- (3) महानिदेशक, नियम 4 के उपनियम(1) में संदर्भित आवेदन की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रसारित करेंगे -
- (क) केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मंत्रालय;
 - (ख) संबंधित व्यापार संघ अथवा उस मूलभूत वस्तु का अभिज्ञात निर्यातक जिसके बढ़े हुए निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति होने या क्षति होने का खतरा पैदा होने की बात कही गई है;
 - (ग) मलेशिया सरकार; और
 - (घ) अन्य इच्छुक पक्षकार को, उसके द्वारा लिखित में अनुरोध किए जाने पर।

(4) महानिदेशक निर्यातकों, उत्पादकों और मलेशिया सरकार को नोटिस जारी करके ऐसे प्रारूप में जानकारी मांग सकता है जो कि वह विनिर्दिष्ट करे और ऐसे नोटिस के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर या ऐसी बड़ाई हुई अवधि के भीतर जिसके लिए पर्याप्त कारण बताये जाने पर महानिदेशक अनुमति दे, ऐसी जानकारी ऐसे व्यक्तियों द्वारा तथा मलेशिया सरकार के द्वारा लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए यह माना जाएगा कि ये उस तारीख के एक हफ्ते बाद प्राप्त हो गई हैं जिस तारीख को महानिदेशक ने ऐसे दस्तावेजों को पंजीकृत डाक से या मलेशिया सरकार के यथोचित राजनायिक प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा है।

- (5) महानिदेशक जांच के अधीन रहने वाली मूल देश की वस्तुओं के औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को और ऐसे मामलों में जहां कि इन वस्तुओं को खुदरा तौर पर सामान्य रूप से बेचा गया है, के प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को ऐसा अवसर दे सकता है कि इस जांच से संबंधित कोई संगत जानकारी है तो वे उन्हें दे सकते हैं।
- (6) महानिदेशक इच्छुक पक्षकारों या इनके प्रतिनिधि को ऐसी जांच से संबंधित कोई सुसंगत जानकारी को मौखिक रूप से देने के लिए अनुमति दे सकते हैं, जब इसे महानिदेशक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर बाद में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (7) महानिदेशक एक पक्षकार द्वारा उनको प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को ऐसे दूसरे पक्षकार को उपलब्ध कराएंगे जो कि इस जांच में भाग ले रहे हों।
- (8) यदि कोई इच्छुक पक्षकार कोई जानकारी पहुंचाने से इंकार करे और ना ही महानिदेशक के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कोई जानकारी दे या जांच में खास तौर से अवरोध पैदा करता है तो महानिदेशक अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को इस प्रकार की सिफारिश कर सकते हैं जिसे वे ऐसी परिस्थितियों में उचित समझे।
- (9) यदि मूलभूत वस्तुओं का आयात ऐसी वस्तुओं के कुल आयात की तुलना में तीन प्रतिशत से कम है तो बिना कोई द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू किए हुए, जांच पड़ताल तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

6. गोपनीय सूचना.— (1) नियम 5 के उप-नियम (1), (3) और (7), नियम 8 के उप-नियम (2) और नियम 10 के उप-नियम (5) में निहित किन्हीं भी बातों के बावजूद ऐसी कोई सूचना जो कि गोपनीय प्रकृति की है या जिसे कारण बताते हुए गोपनीय आधार पर प्रदान किया गया है, महानिदेशक द्वारा उसे गोपनीय समझा जाएगा और उन्हें ऐसी सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए जाए बिना घोषित नहीं किया जाएगा।

(2) महानिदेशक गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से यह कह सकते हैं कि वे इनका गैर गोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों की राय में ऐसी सूचना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो ऐसे पक्षकार महानिदेशक को यह विवरण देंगे कि ऐसी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के बावजूद, यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट होता है कि गोपनीयता के अनुरोध की जरूरत नहीं है या ऐसी जानकारी को देने वाला इस बात को लेकर अनिच्छुक है कि जानकारी को सार्वजनिक किया जाए अथवा इसे सामान्य अथवा सारांश रूप से घोषित किया जाए तो वह ऐसी जानकारी को नजरअंदाज कर सकता है, जब तक कि उसे अन्य यथोचित स्रोतों से यह पता न लग जाए कि ऐसी जानकारी सही है।

7. गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे का निर्धारण.—महानिदेशक घरेलू उद्योग को होने वाली गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे का निर्धारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करेंगे:-

- (क) महानिदेशक उन सभी कारकों का वास्तविक और परिणात्मक रूप से मूल्यांकन करेंगे जिनका उद्योगों की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है विशेष रूप से जैसे कि, मूलभूत वस्तु के निरपेक्ष या तुलनात्मक रूप से आयात में हुई वृद्धि की दर और मात्रा, मूलभूत वस्तु के बढ़े हुए आयात द्वारा लिया गया घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि, तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन; और
- (ख) इस नियम के अन्तर्गत संदर्भित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच से वास्तविक साक्ष्यों के आधार पर, यह नहीं पता चलता है कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती अथवा इसको समाप्त किये जाने के कारण मूलभूत वस्तु के बढ़े हुए आयात और गम्भीर क्षति या उसके खतरे के बीच कोई आकस्मिक संबंध है और जब मूलभूत वस्तु के बढ़े हुए आयात के कारकों के

अलावा अन्य किसी कारकों से घरेलू उद्योग को उसी समय क्षति हो रही हो तो ऐसी क्षति के लिए मूलभूत वस्तुओं के बढ़े हुए आयात को कारण नहीं माना जा सकता है।

8. प्रारम्भिक निष्कर्ष.—(1) महानिदेशक जांच के संबंध में तेजी से कार्रवाई करेंगे और गम्भीर परिस्थितियों में जहां कहीं यह स्पष्ट सक्ष्य है कि बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है अथवा गंभीर क्षति होने का खतरा है और जहां अनंतिम द्वीपक्षीय रक्षोपाय को लागू किये जाने में विलंब किए जाने से ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती तो वे मूलभूत वस्तु के बढ़े हुए आयात के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति होने के खतरे के बारे में प्रारम्भिक निष्कर्ष रिकॉर्ड कर सकते हैं।

(2) महानिदेशक इन प्रारम्भिक निष्कर्षों के बारे में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे और इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति निम्नलिखित को भी भेजेंगे,-

(क) केन्द्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय;

(ख) मलेशिया सरकार।

9. अनंतिम द्वीपक्षीय रक्षोपाय का लागू किया जाना.—(1) केन्द्र सरकार महानिदेशक के प्रारम्भिक निष्कर्षों के आधार पर -

(क) व्यापार करार के अंतर्गत मूलभूत वस्तु पर लगने वाले सीमा-शुल्क की दर को उस तारीख से और कटौती किए जाने को स्थगित कर सकती है, जिस तारीख को द्वीपक्षीय रक्षोपाय किया जाता है; अथवा

(ख) मूलभूत वस्तु पर लगने वाले सीमा-शुल्क की दर में उस स्तर तक बढ़ोत्तरी कर सकती है कि निम्नलिखित में से निम्न दर से अधिक न हो :

(i) द्वीपक्षीय रक्षोपाय लागू किए जाने वाले दिन को मूलभूत वस्तु पर लागू, सीमा-शुल्क की, अत्यंत वरीयता प्राप्त राष्ट्र लागू दर; अथवा

(ii) जांच की अवधि शुरू होने की तारीख से तत्काल पूर्व, मूलभूत वस्तुओं पर लागू सीमा-शुल्क की अत्यन्त वरीयता प्राप्त राष्ट्र लागू दर।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत अपनाए जाने वाले द्विपक्षीय रक्षोपाय इनको लागू किए जाने की तारीख से 200 दिन से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

10. अंतिम निष्कर्ष.—(1) महानिदेशक ऐसी जांच के प्रारम्भ की तारीख से 8 महीने के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर जोकि जांच शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर हो, जिसके लिए केन्द्र सरकार अनुमति दे यह निर्धारण करेंगे कि क्या,-

(क) जांच के अधीन मूलभूत वस्तुओं के बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति हुई है या गम्भीर क्षति होने का खतरा पैदा हुआ है; और

(ख) इस व्यापार करार के अंतर्गत-सीमा शुल्क में कटौती किए जाने अथवा इसे समाप्त किए जाने के कारण मूलभूत वस्तु के बढ़े हुए आयात और गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे के बीच कोई संबंध है।

(2) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपायों के बारे में ऐसी भी सिफारिश करेंगे जो कि गम्भीर क्षति को रोकने या इसका उपचार करने या समायोजन में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त हों।

(3) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपायों की अवधि के बारे में भी अपनी सिफारिशें देंगे:

बशर्ते कि जहां पर इस प्रकार की सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक होगी वहां महानिदेशक इसको लागू किए जाने की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर द्विपक्षीय रक्षोपाय के ऐसे प्रगामी उदारीकरण की भी सिफारिश करेंगे जो कि समायोजन किए जाने की दृष्टि से पर्याप्त होंगे।

- (4) अंतिम निष्कर्ष में तथ्य और कानून और कारणों के सभी मामलों, जिसके कारण निष्कर्ष निकला है, के संबंध में सूचना विहित होगी।
- (5) महानिदेशक अपने अंतिम निष्कर्षों को अधिसूचित करेंगे।
- (6) महानिदेशक अपने अंतिम निष्कर्षों से संबंधित ऐसी अधिसूचना की एक प्रति निम्नलिखित के पास भी भेजेंगे :

- (क) केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय;
- (ख) मलेशिया सरकार।

11. द्विपक्षीय रक्षोपायों का लागू किया जाना.—(1) महानिदेशक की सिफारिश प्राप्त होने पर, अंतिम निष्कर्षों के अंतर्गत आने वाली मूलभूत वस्तु के संबंध में गम्भीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने और समायोजन करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार व्यापार करार के निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन करेगी जिससे कि -

- (क) द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू किए जाने वाले दिन से व्यापार करार के अंतर्गत वस्तु पर लगने वाले सीमा-शुल्क की दर की कटौती को निलंबित किया जाए; अथवा
- (ख) मूलभूत वस्तु पर लगने वाले सीमा-शुल्क की दर में उस स्तर तक बढ़ोत्तरी कर सकती है जो निम्नलिखित के कम-से-कम स्तर से अधिक नहीं हो :
- (i) द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू किए जाने वाले दिन को मूलभूत वस्तु पर लागू, सीमा-शुल्क की, अत्यन्त वरीयता प्राप्त राष्ट्र लागू दर; अथवा
- (ii) जांच की अवधि शुरू होने की तारीख से तत्काल पूर्व, मूलभूत वस्तुओं पर लागू सीमा-शुल्क की अत्यन्त वरीयता प्राप्त राष्ट्र लागू दर।

(2) इन नियमों के अंतर्गत उन वस्तुओं पर कोई द्विपक्षीय रक्षोपाय नहीं लागू होंगे जिन पर कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उप-धारा (1) के अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी वस्तु के बारे में रक्षोपाय शुल्क लागू किए जा रहे हैं तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में इन नियमों के अंतर्गत लागू किए गए वर्तमान द्विपक्षीय रक्षोपाय भी सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उप-धारा (1) के अनुपालन में कार्रवाई किए जाने के पहले समाप्त कर दिए जाएंगे।

(3) द्विपक्षीय रक्षोपाय के समाप्त किए जाने पर, उपाय के अध्यधीन मूलभूत वस्तु पर लगने वाली सीमा-शुल्क की दर वह दर होगी जो समापन की तारीख को व्यापार करार के अंतर्गत लागू होती, यदि द्विपक्षीय रक्षोपाय को कभी भी लागू नहीं किया गया होता।

(4) यदि महानिदेशक के अंतिम निष्कर्ष में द्विपक्षीय रक्षोपायों को लागू करने की सिफारिश नहीं की गई है तो केन्द्र सरकार, महानिदेशक द्वारा दिए गए अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर नियम 10 के अंतर्गत लगाए गए अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय, यदि कोई हो, को वापस लेगी।

12. द्विपक्षीय रक्षोपायों के प्रारम्भ की तारीख.—(1) नियम 9 अथवा नियम 11 के अंतर्गत लागू किए गए रक्षोपाय, इस तरह के रक्षोपाय को लागू करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(2) उप-नियम (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद, जहां कहीं एक अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू किया गया है और जहां कहीं महानिदेशक ने यह निष्कर्ष रिकॉर्ड किया है कि बड़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति पहुंची है अथवा क्षति पहुंचने का अंदेशा है तो इसे नियम 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया

जाएगा कि इस तरह के द्विपक्षीय रक्षोपाय अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय लागू किए जाने अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

13. झूटी की वापसी.—यदि जांच के समाप्त होने के पश्चात किए गए द्विपक्षीय रक्षोपायों के परिणामस्वरूप झूटी की ऐसी दर बनती है जो कि पहले से ही किए गए अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय के परिणामस्वरूप झूटी की दर से कम है तो संग्रहित की गई झूटी के अंतर को आयातक को वापस कर दिया जाएगा।

14. संक्रमण अवधि.—मूलभूत वस्तु के संबंध में कोई भी द्विपक्षीय रक्षोपाय, उस मूलभूत वस्तु की संक्रमणकालीन अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा तथा जो कि व्यापार करार के लागू होने की तारीख से शुरू होकर टैरिफ कटौती के पूरे होने के 7 वर्ष बाद तक अथवा व्यापार करार के अंतर्गत टैरिफ समाप्ति के पूरा होने तक, जैसा भी मामला हो, उस मूलभूत वस्तु के संबंध में होगा।

15. अवधि.—(1) व्यापार करार के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई रियायतों की समाप्ति अथवा नियम 11 के अंतर्गत लागू किए जाने वाले द्विपक्षीय रक्षोपाय केवल उस अवधि के लिए होंगे जो कि गम्भीर क्षति को रोकने अथवा समाप्त करने और समायोजन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक हो।

(2) उप-नियम (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 11 के अंतर्गत लगाए गए द्विपक्षीय रक्षोपाय, इनको लागू किए जाने की तारीख के 2 वर्ष तक ही लागू रहेंगे:

बशर्ते यह कि केन्द्र सरकार महानिदेशक की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात नियम 17 के उप-नियम (1) के अंतर्गत इस तरह लागू किए जाने की अवधि को आगे 2 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है:

बशर्ते कि द्विपक्षीय रक्षोपाय की कुल अवधि जिसमें इनकी बढ़ाई हुई अवधि भी शामिल है, 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) उप-नियम (1) और (2) में विहित किसी भी बात के बावजूद मूलभूत वस्तु के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय की अवधि नियम 14 में यथा उपबंधित मूलभूत वस्तु की संक्रमण अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

(4) इन नियमों के अंतर्गत कोई भी द्विपक्षीय रक्षोपाय ऐसी मूलभूत वस्तु के आयात पर पुनः लागू नहीं होगा जो कि पूर्व में इस प्रकार के द्विपक्षीय उपाय की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे द्विपक्षीय रक्षोपाय के अध्यक्षीन रही है तथा ऐसे द्विपक्षीय रक्षोपाय की अवधि, किसी वस्तु के संबंध में पिछले द्विपक्षीय रक्षोपाय की अवधि से कम होगी।

16. रक्षोपायों का उदारीकरण.—यदि नियम 11 के अंतर्गत लगाए गए द्विपक्षीय रक्षोपायों की अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाती है तो द्विपक्षीय रक्षोपायों को इनके लगाए जाने की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर इनकी बढ़ाई गई अवधि सहित प्रगामी रूप से उदारीकृत किया जाएगा।

17. समीक्षा.—(1) महानिदेशक, द्विपक्षीय रक्षोपायों के निरंतर लागू किए जाने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं और वे उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि-

(क) द्विपक्षीय रक्षोपाय गम्भीर क्षति को रोकने अथवा इसका उपाय करने के लिए आवश्यक हैं और इस बात का साक्ष्य है कि उद्योग समायोजन कर रहा है तो वे द्विपक्षीय रक्षोपायों के निरंतर लगाए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकते हैं;

(ख) ऐसे उपायों को जारी रखने के पीछे कोई औचित्य नहीं है जिनको वापस लिए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश की गई हो।

(2) नियम 4, 5, 6 और 10 के प्रावधान, समीक्षा के मामले में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

[फा. सं. 15021/20/2016-निदे. (आईसीडी)]

सत्यजीत मोहंती, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st June, 2017

No. 55/2017-Customs (N.T.)

G.S.R. 619(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with sub-section (1) of section 25 and section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Director General” means the Director General (Safeguard) appointed by the Central Government under sub-rule (1) of rule 3 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997;
- (b) “domestic industry” means, with respect to an imported good, the producers -
 - (i) as a whole of the like good or directly competitive good in India; or
 - (ii) whose collective production of the like good or directly competitive good in India constitutes a major proportion of the total domestic production of the such good in India;
- (c) “good” means any merchandise, product, article or material;
- (d) “increased imports” means increase in imports from Malaysia whether in absolute terms or relative to domestic production;
- (e) “interested party” includes, -
 - (i) any exporter or producer from Malaysia or importer of the good subjected to investigation for purposes of taking bilateral safeguard measure or a trade or business association, majority of the members of which are producers, exporters or importers of such good;
 - (ii) the Government of Malaysia; and
 - (iii) a producer of the like good or directly competitive good in India or a trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like good or directly competitive good in India;
- (f) “like good” means a good which is identical or alike in all respects to the good under investigation;
- (g) “originating good” means a good which qualifies as an originating good under the provisions of the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Preferential Trade Agreement between the Governments of the Republic of India and Malaysia) Rules, 2011 notified vide notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 43/2011 - Customs (N.T.), dated 1st July, 2011, published vide number G.S.R. 500 (E), dated the 1st July, 2011;
- (h) “serious injury” means a significant overall impairment in the position of a domestic industry;
- (i) “threat of serious injury” means serious injury that is clearly imminent and shall be determined on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility; and
- (j) “Trade Agreement” means the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Malaysia.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the Customs Act, 1962 (52 of 1962) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Duties of Director General.— It shall be the duty of the Director General, -

- (a) to investigate whether increased imports of an originating good into India have caused or are

threatening to cause serious injury to a domestic industry as a result of reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement;

- (b) to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that domestic industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by the increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses and employment;
- (c) to submit his findings, provisional or otherwise, to the Central Government as to the “serious injury” or “threat of serious injury” to domestic industry caused by increased import of an originating good from Malaysia as a result of reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement;
- (d) to recommend bilateral safeguard measure which if adopted would be adequate to prevent or remedy serious injury;
- (e) to recommend the duration of the bilateral safeguard measure and where the period so recommended is more than one year, to recommend progressive liberalisation necessary to facilitate adjustment; and
- (f) to review the need for continuation of a bilateral safeguard measure.

4. Initiation of Investigation.—(1) The Director General shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producer of like good or directly competitive good, initiate an investigation to determine the existence of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry, caused by increased imports of an originating good as result of the reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement.

(2) An application under sub-rule (1) shall be supported by,-

- (a) evidence of -
 - (i) increased imports of the originating good;
 - (ii) serious injury or threat of serious injury to the domestic industry;
 - (iii) a causal link between imports and the alleged serious injury or threat of serious injury; and
 - (iv) the reduction or elimination of a customs duty pursuant to the Trade Agreement being a cause which contributes significantly to the increase in imports of the originating good and such increase in imports is a cause of serious injury or threat of serious injury to domestic industry:

Provided that the cause of reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement need not be equal to or greater than any other cause; and
- (b) a statement on the efforts being made, or planned to be made, or both, to make an adjustment to import competition.

(3) The Director General shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless he examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies himself that there is sufficient evidence regarding-

- (a) increased imports of the originating good;
- (b) serious injury or threat of serious injury;
- (c) a causal link between imports of the originating good and the alleged serious injury or threat of serious injury; and
- (d) the reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement being a cause which contributes significantly to the increase in imports of the originating good:

Provided that the cause of reduction or elimination of a customs duty pursuant to the Trade Agreement need not be equal to or greater than any other cause.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Director General may initiate an investigation *suo motu* if he is satisfied with the information received from any Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as referred to in clause (a), clause (b), clause (c) and clause (d) of sub-rule (3).

5. Principles governing Investigations.—(1) The Director General shall, after he has decided to initiate investigation to determine the serious injury or threat of serious injury to domestic industry, consequent upon the increased imports of an originating good into India as a result of the reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement, issue a public notice notifying the decision thereto and such public notice shall, inter alia, contain adequate information on the following, namely:-

- (a) a precise description of the originating good subject to the investigation and its classification under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
 - (b) the date of initiation of the investigation;
 - (c) the period subject to the investigation;
 - (d) a summary statement of the facts on which the allegation of serious injury or threat of serious injury is based;
 - (e) reasons for initiation of the investigation;
 - (f) the address to which representations by interested parties should be directed; and
 - (g) the time-limits allowed to interested parties for providing their views through appropriate representation.
- (2) The Director-General shall forward a copy of the public notice to:-
- (a) the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, as he deems fit;
 - (b) the concerned trade associations or the known exporters of the originating good, the increased import of which has been alleged to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry;
 - (c) the Government of Malaysia; and
 - (d) any other interested parties, as the Director General deems fit.
- (3) The Director General shall also provide a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 4 to -
- (a) the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry;
 - (b) the concerned trade associations or the known exporters of the originating good, the increased import of which has been alleged to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry; and
 - (c) the Government of Malaysia; and
 - (d) any other interested party upon request in writing.
- (4) The Director General may issue a notice, calling for any information in such form as may be specified in the notice from the exporters, producers and Government of Malaysia and such information shall be furnished by such persons and Government of Malaysia in writing within thirty days from the date of receipt of the notice or within such extended period as the Director General may allow on sufficient cause being shown.
- Explanation:** For the purpose of this rule, the public notice and other documents shall be deemed to have been received one week after the date on which these documents were sent by the Director General by registered post or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the Government of Malaysia.
- (5) The Director General may also provide opportunity to the industrial users of the originating good under investigation and to representative consumer organisations in cases where the originating good is commonly sold at retail level to furnish information which is relevant to the investigation.
- (6) The Director General may allow an interested party or its representative to present the information relevant to investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the Director General only when it is subsequently submitted in writing, within the time frame prescribed by the Director General.
- (7) The Director General shall make available the evidence presented to him by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation.
- (8) In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within the period specified by the Director general or significantly impedes the investigation, the Director General may record the findings on the basis of the facts available to him and make such recommendations to the Central Government as he deems fit under such circumstances.
- (9) The investigation shall be promptly terminated without any bilateral safeguard measure being applied if imports of the originating good from Malaysia represent less than three per cent. of total imports of the good.

6. Confidential information.-(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (3) and (7) of rule 5, sub-rule (2) of rule 8 and sub-rule (5) of rule 10, any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the Director General and shall not be disclosed without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The Director General may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, the same cannot be summarised, such party may submit to the Director General a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is unwilling either to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, he may disregard such information unless it is demonstrated to his satisfaction from appropriate sources that such information is correct.

7. Determination of serious injury or threat of serious injury.- The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, *inter alia*, the following principles, namely :-

- (a) the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that domestic industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses and employment; and
- (b) the determination referred under this rule shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the originating good due to reduction or elimination of a customs duty pursuant to the Trade Agreement and serious injury or threat thereof and when factors other than increased imports of the originating good are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports of the originating good.

8. Preliminary findings.- (1) The Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, where there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry and where delay in imposition of provisional bilateral safeguard measure would cause damage which would be difficult to repair, may record a preliminary findings regarding serious injury or threat of serious injury to the domestic industry as a result of increased imports of an originating good.

(2) The Director General shall issue a public notice regarding such preliminary findings and send a copy of the public notice to,-

- (a) the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and in the Ministry of Finance;
- (b) the Government of Malaysia.

9. Application of provisional bilateral safeguard measure.-(1) The Central Government, on the basis of the preliminary findings of the Director General, may -

- (a) suspend further reduction of any rate of customs duty on the originating good provided for under the Trade Agreement from the day when the bilateral safeguard measure is taken; or
- (b) increase the rate of customs duty on the originating good to a level not to exceed the lesser of:
 - (i) the Most Favoured Nation applied rate of custom duty on the originating good in effect on the day when the bilateral safeguard measure is taken; or
 - (ii) the Most Favoured Nation applied rate of custom duty on the originating good in effect on the day immediately preceding the date of the start of the period of investigation.

(2) The bilateral safeguard measure under sub-rule (1) shall remain in force only for a period not exceeding two hundred days from the date of its imposition.

10. Final findings.-(1) The Director General shall, within eight months from the date of initiation of the investigation, or within an extended period not exceeding one year from the date of initiation of the investigation, as the Central Government may allow, determine whether, -

- (a) the increased imports of the originating good under investigation have caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry; and
- (b) a causal link exists between the increased imports of the originating good due to the reduction or elimination of a customs duty pursuant to the Trade Agreement and serious injury or threat of serious injury.

(2) The Director General shall also give his recommendation regarding the bilateral safeguard measure which would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.

(3) The Director General shall also make his recommendations regarding the duration of the bilateral safeguard measure:

Provided that where the period recommended is more than one year, the Director General shall also recommend progressive liberalisation of the bilateral safeguard measure at regular intervals during the period of its application, adequate to facilitate adjustment.

- (4) The final findings shall contain information on all matters of fact and law and reasons which have led to the conclusion.
- (5) The Director General shall notify his final findings.
- (6) The Director General shall send a copy of the such notification of final findings to:
 - (i) the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and in the Ministry of Finance;
 - (ii) the Government of Malaysia.

11. Application of bilateral safeguard measure.-(1) On receipt of the recommendation of the Director General, in order to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment in respect of the originating good covered under the final findings, the Central Government may suitably amend the notification, issued under sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) to give effect to the provisions of the Trade Agreement, so as to -

- (a) suspend further reduction of any rate of customs duty on the originating good provided for under the Trade Agreement from the day when the bilateral safeguard measure is taken; or
- (b) increase the rate of customs duty on the originating good to a level not to exceed the lesser of:
 - (i) the Most Favoured Nation applied rate of custom duty on the originating good in effect on the day when the bilateral safeguard measure is taken; or
 - (ii) the Most Favoured Nation applied rate of custom duty on the originating good in effect on the day immediately preceding the date of the start of the period of investigation.

(2) No bilateral safeguard measure under these rules may be imposed in respect of a good on which actions under sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) is in place and in the event of a safeguard duty being imposed in respect of a good under sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), any existing bilateral safeguard measure which has been imposed under these rules in respect of that good shall be terminated prior to the imposition of the action under the sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(3) On termination of a bilateral safeguard measure, the rate of customs duty for an originating good subject to the measure shall be the rate which would have been in effect under the Trade Agreement on the date of termination as if the bilateral safeguard measure had never been applied.

(4) In case, in the final finding of the Director General there is no recommendation for applying bilateral safeguard measure, the Central Government shall within thirty days of the publication of final findings by the Director General under rule 10, withdraw the provisional bilateral safeguard measure imposed, if any.

12. Date of commencement of bilateral safeguard measure.-(1) The bilateral safeguard measure under rule 9 or rule 11 shall come into effect from the date of publication of the notification, in the Official Gazette.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a provisional bilateral safeguard measure has been imposed and where the Director General has recorded a finding that increased imports have caused or threaten to cause serious injury to domestic industry, it shall be specified in the notification issued under rule 11 that such bilateral safeguard measure shall take effect from the date of notification imposing the provisional bilateral safeguard measure.

13. Refund of duty.- If the bilateral safeguard measure taken after the conclusion of the investigation results in a rate of duty which is lower than the rate of duty resulting from a provisional bilateral safeguard measure already taken, the differential duty collected shall be refunded to the importer.

14. Transition period.-No bilateral safeguard measure on an originating good shall be taken after expiry of the transition period for that originating good which shall be from the date of entry into force of the Trade Agreement till seven years after the date of completion of tariff reduction or completion of tariff elimination under the Trade Agreement, as the case may be for that originating good.

15. Duration.-(1) The suspension of the concessions granted under the provisions of the Trade Agreement or the bilateral safeguard measure applied under rule 11 shall be only to the extent and for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a bilateral safeguard measure applied under rule 11 shall not exceed a period of two years from the date of its imposition:

Provided that the Central Government may, on the receipt of recommendation of the Director General under sub-rule (1) of rule 17, extend the period of such imposition by a further period up to two years:

Provided further that the total duration of the bilateral safeguard measure, including such extensions, shall not exceed four years.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2), the duration of bilateral safeguard measure on an originating good shall terminate at the end of the transition period for such originating good as specified in rule 14.

(4) No bilateral safeguard measure under these rules shall be applied again to the import of an originating good that has previously been subject to such bilateral safeguard measure for a period of one year from the date of expiry of the bilateral safeguard measure and the duration of such bilateral safeguard measure shall be less than the duration of the previous bilateral safeguard measure on the same good.

16. Liberalisation of safeguard measure.—If the duration of the application of bilateral safeguard measure under rule 11 is more than one year, the bilateral safeguard measure shall be progressively liberalised at regular intervals during the period of its application, including the period of its extension.

17. Review.—(1) The Director General may review the need for continued application of the bilateral safeguard measure and, if he is satisfied on the basis of information received that -

- (a) the bilateral safeguard measure is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting, he may recommend to the Central Government for the continued imposition of bilateral safeguard measure;
- (b) there is no justification for the continued imposition of such measure, recommend to the Central Government for its withdrawal.

(2) The provisions of rules 4, 5, 6 and 10 shall mutatis mutandis apply in the case of review.

[F. No. 15021/20/2016 - Dir (ICD)]

SATYAJIT MOHANTY, Director